नक्सलियों का फिर दुस्साहस

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बुधवार को नक्सलियों के हमले में पुलिस के 15 जवानों की मौत चिंताजनक है। यह साफ है कि हालात काबू में नहीं हैं और नक्सली पूरी ताकत के साथ हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वे आए दिन वाहनों को फूंक रहे हैं, सड़क बनाने में लगी मशीनों को आग के हवाले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। क्या ये सब मामूली घटनाएं हैं? क्या सरकार के लिए यह गंभीर चुनौती नहीं है? सवाल है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है और सरकार नक्लसियों से निपटने में सफल रही है, जैसा कि हमेशा दावा किया जाता रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? इससे लगता है सरकार का खुफिया तंत्र नाकाम है और उसे नक्सलियों के हमलों की भनक तक नहीं लगती। लेकिन बुधवार के इस दहला देने वाले हमले के बाद महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक ने खुफिया नाकामी की बात से साफ इनकार कर दिया। सवाल है कि अगर जरा भी खबर होती कि नक्सली आइईडी से हमला करने वाले हैं तो क्या जवानों को ले जा रहा वाहन वहां से गुजरने दिया जाता! मगर सच यह है कि नक्सलियों ने यह हमला करके खुफिया तंत्र की पोल खोल दी है।

गढ़चिरौली जिले में जहां यह हमला हुआ है वह जगह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमा से सटा इलाका है। नक्सलियों ने हमले से कुछ घंटे पहले इस इलाके में सड़क निर्माण ठेकेदार की मशीनों और वाहनों को आग लगा दी थी। इसकी खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो दो बसों में सवार में होकर मौके पर जा रहे थे। उसी समय नक्सलियों ने बारूदी सुरंग को उड़ा डाला। नक्सली इन इलाकों में निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि सड़कों का नेटवर्क खड़ा हो जाने के बाद उनके खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान और तेज हो जाएंगे। बुधवार को हमले के वक्त मौके पर करीब दो सौ नक्सली मौजूद थे। हालांकि पिछले साल अप्रैल में पुलिस ने 40 नक्सलियों को मार गिराया था। तब सरकार ने दावा किया था कि नक्सली अब सिर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन एक साल बाद फिर से नक्सलियों ने बड़ा हमला कर अपनी मौजूदगी और ताकत का संदेश देने की कोशिश की है। पिछले महीने नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भाजपा विधायक और चार पुलिस वालों की हत्या कर दी थी।

दो साल पहले माओवादी हिंसा से प्रभावित दस राज्यों में एकीकृत कमान के गठन की पहल भी हुई थी और सभी राज्यों की साझा रणनीति बना कर आठ सूत्री समाधान भी तैयार किया गया था, लेकिन

> महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बुधवार को नक्सलियों के हमले में पुलिस के 15 जवानों की मौत चिंताजनक है। यह साफ है कि हालात काबू में नहीं हैं और नक्सली पूरी ताकत के साथ हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। चुनाव के समय हर सरकार यह दिखाना चाहती है कि नक्सलवाद पर काफी हद तक लगाम लग गई है, इसलिए उसकी नीतियां भी बदलती रहती हैं और यही वजह है कि नक्सलवाद के खिलाफ कोई मजबूत और स्थिर नीति नहीं बन पाई है।

बुनियादी समस्या यह है कि नक्सलवाद से निपटने की योजनाएं जिस प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए, लगता है वे हो नहीं रहीं। सत्ता तंत्र के इस रवैए से लगता है कि वह इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में सारी कवायद निष्फल साबित होती है। इसमें पैसा और समय तो जाता ही है, समस्या और गहराती जाती है। नक्सल समस्या दशकों पुरानी हो चुकी है। अगर इतने सालों में भी पिछड़े इलाकों में विकास नहीं हो पाया है और नक्सलियों का दबदबा बना हुआ है तो इसके लिए सीधे-सीधे राज्य और केंद्र सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर नक्सलियों की समांतर सत्ता कायम है तो यह उनकी कामयाबी से कहीं ज्यादा हमारे शासन तंत्र की नाकामी का सबूत है। वरना ऐसे बड़े हमले बार-बार नहीं होते!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जवानों की बहादुरी पर हमें गर्व है लेकिन इस हमले के बाद कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन्हें लंबे वक्त से नजर अंदाज किया जा रहा है और काम नहीं हो रहा है। क्या नक्सलियों से निपटने की जो नीति राज्य और केंद्र सरकार अपना रही है वो काफी है? आखिर कहां चूक हो रही है जो इस तरह के हमले आए दिन सामने आ जाते हैं। हमें उन बिंदुओं पर भी बात करनी होगी, जिससे नक्सली हमलों पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है। नक्सलियों से निपटना है तो स्थानीय लोगों को साथ लेने की जरूरत है। नक्सली हमलों में जिस तरह पुलिस और केंद्रीय बल को निपटना चाहिए उस तरह की कोशिश होती नहीं दिख रही है। नक्सली हमला जब भी होता है तो पूर्व सुनियोजित तरीके से होता है। हमलावरों को पता होता है कि किस वक्त हमला करने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ऐसे में जरूरी है कि पुलिस और सीआरपीएफ स्थानीय लोगों को अपने साथ ले ताकि ऐसे ऑपरेशंस में सूचना तंत्र और बेहतरी से काम कर सके।

पुलिस-सुरक्षा बलों को नक्सलियों से मिलकर लड़ना होगा। नक्सलवाद से लड़ने की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ और राज्य पुलिस दोनों की है, ऐसे में जरूरी है कि दोनों के बीच आपसी तालमेल बेहतर हो। स्थानीय स्तर पर पुलिस के पास सीआरपीएफ के मुकाबले बेहतर सूचना तंत्र है और इसलिए जरूरी है कि पुलिस आगे रहे और सीआरपीएफ पुलिस का साथ दे। लेकिन देखा यह गया है कि इस मोर्चे पर सुरक्षा बल पुलिस से आगे हैं, दोनों के बीच इंटेलिजेंस की कोई कड़ी नहीं है। पुलिस अपने स्तर पर काम करती है और सीआरपीएफ अपने स्तर पर। आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के ऑपरेशंस में पुलिस लड़ाई में आगे होती है और केंद्रीय बल उसको समर्थन देते हैं। अधिकारियों में भ्रष्टाचार भी नक्सली हमलों की एक प्रमुख वजह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नक्सलवाद के खिलाफ हो रही तमाम कोशिशों में से सबसे कारगर कोशिश विकास है। प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए बड़ी रकम भेजी जाती है जिसमें स्कूल, नागरिक सेवाएं, बिजली, पानी-सड़क शामिल हैं लेकिन जिन अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी है उनके भ्रष्टाचार के चलते आम लोगों तक ये सहूलियतें नहीं पहुंच पाती।

राज्य सरकारों की अलग-अलग नीतियां भी नक्सली हमलों की बड़ी वजह हैं। नक्सलवाद भारत के लिए लंबे समय से चुनौती रही है। ये समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि देश के 8 राज्यों के 60 ज़िलों की है। इनमें ओडिशा के 5, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10, मध्यप्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 और बंगाल के 8 जिले आते हैं। जाहिर है इस समस्या पर सभी राज्यों को मिलकर एक सख्त नीति बनाने की जरूरत है ताकि व्यापक तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ देश की नीति को परिभाषित किया जा सके। जबकि हकीकत यह है कि राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर इस चुनौती से लड़ती हैं। ऐसा कोई तय एक्शन प्लान नहीं है जिसके जरिए नक्सलवाद की समस्या का सामना किया जाए। इस मामले में समस्या ये भी है कि नक्सलवादी हमलों को अबतक सिर्फ कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है लिहाजा इस चुनौती के लिए पूरी तरह से राज्य सरकारों को ही फैसला लेना होता है, केंद्र मामले में सिर्फ मदद कर सकता है।

चुनाव के समय हर सरकार ये दिखाना चाहती है कि नक्सलवाद पर काफी हद तक लगाम लग गई है, इसलिए उसकी नीतियां भी बदलती रहती हैं और यही वजह है कि नक्सलवाद के खिलाफ कोई मजबूत और स्थिर नीति नहीं बन पाई है, जिसका नतीजा गढ़चिरौली में हुए हमले के तौर पर सामने आता है और हम पर सवाल खड़े कर जाते है।

चिंतन

मसूद अजहर पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी लगने के बावजूद पाक आसानी से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा

पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी लगना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। यह कामयाबी हासिल करने में एक दशक इसीलिए लग गए, क्योंकि चीन इस आतंकी सरगना की ढाल बना हुआ था।

उसने अपना अड़ियल रवैया तब छोड़ा जब उसके सामने यह स्पष्ट हो गया कि भारत इस मामले को छोड़ने वाला नहीं और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के चलते उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो सकती है। इसमें दोराय नहीं कि भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान तमाम शर्मिंदगी उठाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं।

संसद और पठानकोट एयरबेस समेत पुलवामा में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी लगने के बावजूद आसार इसी के हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बने आतंकियों को पालने-पोसने की अपनी नीति का परित्याग न करे।

अंदेशा इसका भी है कि वह मसूद अजहर पर उसी तरह की दिखावटी सख्ती करे जैसे उसने एक अन्य आतंकी सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कथित तौर पर कर रखी है। आखिर यह एक तथ्य है कि पाकिस्तान सरकार और खासकर उसकी सेना एवं खुफिया एजेंसी आइएसआइ अपने यहां फल-फूल रहे आतंकियों के खिलाफ कुछ न करने और दबाव पड़ने पर कार्रवाई का दिखावा कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है। हैरत नहीं कि पाकिस्तानी सेना मसूद अजहर को और संरक्षित करने का काम करे। पाकिस्तान पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने यह कहकर अपनी झेंप मिटाने और साथ ही अपनी जनता को भरमाने की कोशिश की है कि मसूद अजहर पर पाबंदी के बावजूद उसकी जीत हुई, क्योंकि सुरक्षा परिषद के फैसले में पुलवामा हमले का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के ऐसे रवैये को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत और अमेरिका इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें कि पाकिस्तान वास्तव में मसूद अजहर पर लगाम लगाए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो फिर उसकी चालबाजी के पुख्ता सुबूत एकत्र करके उन्हें एफएटीएफ के समक्ष रखने चाहिए। इस अंतरराष्ट्रीय संस्था की अगली बैठक में इस पर विचार होना है कि पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को पालने के लिए काली सूची में रखा जाए या नहीं? पाकिस्तान पिछली बैठक में काली सूची में जाने से बच गया था। अगली बार भी चीन उसके बचाव में आ सकता है।

यदि पाकिस्तान काली सूची में दर्ज होने से फिर बच जाता है तो वह आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का काम तेज कर सकता है।

चूंकि पाकिस्तान के रंग-ढंग बदलने की ज्यादा उम्मीद नहीं इसलिए भारत को उसकी हरकतों को लेकर न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि उस पर यह दबाव भी बढ़ाना होगा कि वह आतंकवाद का सहारा लेना छोड़े। नि:संदेह इसी के साथ ऐसे भी उपाय करने होंगे जिससे पाकिस्तान कश्मीर में दखल देने में सक्षम न रहे।